

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 21 / 2017 / जैसलमेर

अपीलांत

रेस्पोंडेंटगण

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान बनाम 1. मोटूदान पुत्र स्व. सीताराम
तहसीलदार फतेहगढ़ जिला 2. जीवणदान पुत्र स्व. सीताराम
जैसलमेर। 3. चमदान पुत्र स्व. सीताराम
4. मोहनदान पुत्र स्व. सीताराम जातियान
चारण निवासी कोडा तहसील फतेहगढ़
जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर फतेहगढ़ के राजस्व वाद संख्या 96/2015 बअनवान सीताराम कायम मुकाम मोटूदान वगैरह बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2016 के विरुद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्त की ओर से
2. रेस्पोंडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक:- 22.08.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोंडेंट के हक में ग्राम कोडा के वर्तमान खसरा नम्बर 161 रकबा 22.07 बीघा व खसरा संख्या 342 रकबा 53.06 बीघा कुल रकबा 75.13 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया है जबकि यह भूमि सेटलमेंट में भी सरकारी भूमि दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियों प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोंडेंट द्वारा कोई आपति पेश नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू-प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोंडेंट का कोई कब्जा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

नहीं है न ही कोई अभिलेखीय कब्जा साबित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 29.06.2016 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। राजकीय अभिभाषक की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोंडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोंडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोंडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नहीं की गई। इसलिए अब रेस्पोंडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। भू-प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनापने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने व प्रार्थी कर अन्य प्रशासनिक कार्यों में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।



प्रार्थी के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को विचारण के दौरान प्रदर्शित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में तनकीयात कायम नहीं की गई है तथा तनकीवार निर्णय भी पारित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित वाद विचारण की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। प्रक्रियागत कमी होने से अपीलाधीन निर्णय प्रथम दृष्टया दूषित प्रतीत होता है। लिहाजा मामला रिमाण्ड योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
वाइमेर

अतः अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ़ के राजस्व वाद संख्या 96/2015 बअनवान सीताराम के कायम मुकाम मोदूदान वगैरह बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2016 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में तनकीयात कायम कर बाद विधिवत रूप से साक्ष्य रिकॉर्ड पर ली जाकर तनकीवार विवेचन करते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करे अर्थात् प्रस्तुत दस्तावेजात को प्रदर्श कराते हुए विधि सम्मत गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।



यह आदेश आज दिनांक 22.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/8/19
राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

22/8/19
राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर